उत्तराखण्ड विधान सभा

प्रथम सत्र, 2019
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

बुधवार,

माघ 24, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 13 फरवरी 2019)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित

श्री कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन
29.01.2019

'' क्या गन्ना मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के खादर क्षेत्र में गन्ने की दो स्वीकृत प्रजातियों क्रमशः (1) अगेती प्रजाति एवं (2) सामान्य प्रजाति के अलावा तीसरी प्रजाति अनुपयुक्त प्रजाति का गन्ना भौगोलिक सीमितताओं के कारण उगाया जाता है लेकिन सरकार द्वारा उक्त प्रजाति का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है जिस कारणवश खादर के किसानों को वह गन्ने की फसल मजबूरी में बहुत कम दाम पर बेचनी पड़ रही है, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उक्त प्रजाति का मूल्य दो माह पूर्व तय कर दिया गया है? क्या राज्य सरकार लोकहित में खादर क्षेत्र के किसानों को नुकसान और शोषण से बचाने हेतु अविलम्ब अनुपयुक्त प्रजाति के गन्ना मूल्य की घोषणा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **गन्ना**

श्री देशराज कर्णवाल
01.02.2019

'' क्या गन्ना मंत्री अवगत हैं कि पूरे राज्य में गन्ना किसान गन्ना मूल्य भुगतान न होने के कारण आन्दोलन करने के लिए विवश रहते है इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए जिससे कि प्रतिवर्ष उनका भुगतान सुनिश्चित हो सके, के लिए क्या सरकार उत्तराखण्ड के किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कोष बनाने की एक बहुउद्देशीय योजना का स्वरूप सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **गन्ना**

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल
28.12.2018

'1 क्या कौशल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रोजगार सृजन एवं कौशल विकास विभाग बनाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, **कौशल विकास**

तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देशराज कर्णवाल
31.12.2018

'2 क्या कौशल विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए खोले गये कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कितने कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं तथा इन्हें किन–किन संस्थानों को आवंटित किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में कितने कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हो रहे है तथा इनमें क्या कोई गडबड़ी पायी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों/केन्द्रों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

कौशल विकास

श्री देशराज कर्णवाल
02.01.2019

'3. क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों के पर्यावरण मानकों की समय–समय पर जॉच हेतु सरकार की काई नीति है अथवा नहीं? यदि हॉ तो हरिद्वार की कितनी फैक्ट्रियों में जॉच की गई है तथा उन फैक्ट्रियों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

पर्यावरण

श्री नवीन चन्द्र दुम्का
03.01.2019

प्रथम मंगलवार के तारांकित 19 में स्थानान्तरित।

'4. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि अनु0 जनजाति और अन्य परमपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 2 वर्ष 2007) की धारा 6 की उपधारा–3 के अर्न्तगत जिलास्तरीय, उपखण्ड स्तरीय समिति बनाने का प्रावधान है? यदि हॉ, तो क्या जनपद नैनीताल में भी कोई समिति गठित है? यदि हॉ, तो उत्तराखण्ड गठन के बाद जनपद नैनीताल में समिति ने कोई कार्य किया है?

वन

श्री खजानदास
08.01.2019

'5 क्या सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड प्रदेश में कुल कितने सेवायोजन कार्यालय हैं तथा राज्य निर्माण के गठन से अब तक कुल कितने बेरोजगारों को सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार मिला है तथा जिलेवार बेराजगारों की कुल कितनी संख्या है? क्या सरकार प्रदेश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्रदान किये जाने हेतु कोई ठोस नीति बनायेगी?यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सेवायोजन

श्री खजानदास
09.01.2019

'6 क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि प्रदेश में ए0डी0बी0 के द्वारा विभिन्न शहरों में निर्मित सीवर लाईनें एवं पेयजल योजनायें सुचारू रूप से कार्य कर रही है अथवा नहीं? यदि हॉ, तो किन–किन शहरों में योजनायें सुचारू रूप से कार्य कर रही है एवं किन–किन शहरों में अब तक भी योजनायें जल संस्थान को स्थानान्तरित नहीं हो पाई है? क्या सरकार अपूर्ण एवं अधूरी योजनायें समय अवधि में पूर्ण न होने एवं गुणवत्ता विहीन योजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं के विरूद्व कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शहरी विकास

श्री खजानदास
09.01.2019

एक से अधिक विभागों से संबंधित होने के आधार पर निरस्त।

'7 क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड़ प्रदेश भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है? क्या सरकार द्वारा भूकम्प से होने वाली जनहानि को रोकने हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों/ शहरों में गिरासू भवनों का चिन्हीकरण किया जा चुका है? क्या सरकार द्वारा गिरासू भवनों का रखरखाव/पुर्ननिर्माण एंव भूकम्प आने पर कम से कम जनधन की हांनि हो, इस हेतु कोई ठोस नीति बनाई जा रही है अथवा नहीं? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शहरी विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार
10.01.2019

'8 क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न उद्योगों मे कार्यरत किन–किन औद्योगिक श्रमिकों तथा उनके मृतक आश्रितों को वर्ष 2016–17 में न्यूनतम वेतन, क्षतिपूर्ति एवं ग्रेच्यूटी आदि की कुल कितनी धनराशि का भुगतान विभाग के द्वारा किया गया? क्या सरकार बतायेगी कि उत्तराखण्ड में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर लिया गया है? यदि हां, तो न्यूनतम मजदूरी क्या निर्धारित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
14.01.2019

'9. क्या वन मंत्री अवगत है, कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों जैसे बन्दर, सुअर आदि का अत्याधिक प्रकोप होने के कारण स्थानीय कृषकों की फसल नष्ट कर हो जाती है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों ने कृषि करना छोड दिया है, जिससे उनका जीवोकोपार्जन करना भी बहुत कठिन हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कृषकों के लिए कोई योजना बना रही है, जिससे कृषकों की फसल नष्ट होने पर उनको उसका लाभ मिल सके? क्या सरकार जंगली जानवरों द्वारा नष्ट की गयी फसल को मुआवजों का भुगतान करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
14.01.2019

'10. क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं तथा उसके सापेक्ष कुल कितने पंजीकृत बरोजगारों को रोजगार दिया गया है?क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में सभी पंजीकृत बरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां तो तद्संबंधी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नही तो क्यों?

सेवायोजन

श्री गणेश जोशी
14.01.2019

मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

'11. क्या आवास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून में कई स्थानों में आवास विकास कालोनी के अर्न्तगत होटल संचालित किये जा रहे है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसे होटल किसी प्राधिकरण अथवा सक्षम स्तर से अनुमति के बाद खोले गये है? यदि हां, तो सरकार जनपद देहरादून के ऐसे होटलों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे होटलों को सीज करने अथवा ध्वस्त करने पर विचार

आवास

करेगी?

श्री मनोज रावत
14.01.2019

'12. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि राज्य सरकार की श्रमिकों के कल्याण हेतु क्या–क्या योजनाऐं हैं? इन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु योजनावार कितना धन विभिन्न मदों में रखा गया है? आतिथि जिले वार कितने श्रमिक, इन योजनाओं हेतु पंजीकृत किए गए हैं तथा सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु इन विभिन्न योजनाओं में गत दो वर्षों में अलग–अलग कितना–कितना धन आवंटित किया गया है? **श्रम**

श्री प्रीतम सिंह पंवार
16.01.2019

आगामी सत्र हेतु स्थगित

'13 क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि राज्य में जो उपग्राम, बस्तियां, राजस्व ग्राम तथा ग्राम पंचायते, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगमों में शामिल की गई है, ऐसे गांवो में विकास योजनाओं के कियान्वयन के लिए कोई अतिरिक्त बजट अथवा राजकीय अनुदान सरकार द्वारा विशेष पैकेज के रूप मे स्वीकृत कर जारी किया गया है? क्या यह भी सत्य है कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले बजट से यह क्षेत्र वंचित हो गये है और नगर निकायों द्वारा भी विकास कार्य ऐसे ग्रामों/क्षेत्रों में नहीं कराये जा रहे हैं? क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में विशेष विकास योजनाओं का कार्यक्रम संचालित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **शहरी विकास**

श्री प्रीतम सिंह पंवार
16.01.2019

'14 क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश भूभाग वनाच्छादित है और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश ग्रामीणों के द्वारा दशको पूर्व से वन भूमि पर खेतीबाडी, उद्यान तथा आवास / गौशालायें बनायी गई है? गरीब तथा भूमिहीन काश्तकारों के द्वारा अपनी आजीविका लम्बे काल से ऐसी भूमि पर काबिज होकर चलायी जा रही है? क्या सरकार ऐसे गरीब तथा भूमिहीन काश्तकारो से नजराना लेकर उन्हें वह भूमि उनके नाम दर्ज करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **वन**

श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण
16.01.2019

'15 क्या वन मंत्री अवगत हैं कि सरकार द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश जारी किया गया था कि गंगा और उसकी सहायक नदियों मे सीधे कूडा एवं सीवरेज डालने वाले होटलों, धर्मशालाओं व आश्रमों से प्रतिदिन रूपये 5000 की दर से जुर्माना वसूला जाये? यदि हां, तो अब तक कितने संस्थानों से कुल कितनी राशि का जुर्माना वसूला गया है? यदि नहीं, तो क्यों? **वन**

श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण
17.01.2019

'16 क्या वन मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड में वन पंचायतें वित्तीय संसाधनों का अभाव झेल रही हैं इन वन पंचायतों को आर्थिक मदद प्रदान करने हेतु राज्य सरकार और जायका (जापान इन्टरनेशनल को–आपरेटिव) मार्च, 2022 तक एक परियोजना संचालित करेंगे? यदि हॉ, तो यह परियोजना यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र की कितनी वन पंचायतों में संचालित की जायेगी? इन वन पंचायतों में किस प्रकार के रोजगारपरक कार्यक्रम चलाये जायेंगे? जिन–जिन पंचायतों को इस परियोजना में शामिल नहीं किया गया है, उनके लिये सरकार की क्या योजना है? **वन**

श्री मनोज रावत
18.01.2019

'17 क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के वन विभाग ने बंदरों, सुअरों और अन्य जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा करने हेतु कोई उपाय किए हैं? क्या राज्य के वन विभाग ने खेती को नुकसान करने वाले जानवरों की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए देश और राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों को वैज्ञानिक उपाय करने हेतु सम्पर्क किया है? यदि हॉ, तो जंगली जानवरों की जनसंख्या नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार के पास कोई वैज्ञानिक उपाय है? यदि नही तो राज्य सरकार इस दिशा में प्रयास करेंगी? यदि हॉ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
23.01.2019

'18 क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत शीशमबाड़ा में ट्रेंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण किया गया है? ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण से पूर्व में क्षेत्रवासियों को ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में कूड़ा निस्तारण के समय दुर्गन्ध आने से क्षेत्र में गम्भीर बीमारियां उत्पन्न होने व नदी का पानी दूषित होने, पर्यावरण को भी नुकसान होने का अंदेशा था? पूर्व में क्षेत्रवासियों के विरोध के बावजूद भी ट्रेंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण कर दिया गया? वर्तमान में ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया शुरू होने एवं कूड़े से निकलने वाली दुर्गन्ध से ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के चारों ओर लगभग 8–10 कि0मी0 के दायरे में दुर्गन्ध से कई गांव प्रभावित हो रहे हैं? क्षेत्रवासियों द्वारा संबंधित कूड़ा निस्तारण कम्पनी व संबंधित विभाग को मौखिक व लिखित व आन्दोलन के रूप में वायु के साथ फैलने वाली दुर्गन्ध के निस्तारण हेतु कई बार अवगत कराया गया लेकिन आतिथि तक भी ट्रेंचिंग ग्राउण्ड से निकलने वाली दुर्गन्ध का कोई उपाय नहीं किया गया और टेंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण मानकों की अनदेखी कर किया गया है? क्या निर्माण में मानकों की अनदेखी व उससे निकलने वाली दुर्गन्ध व अन्य समस्याओं से निजात दिलाये जाने हेतु ट्रेंचिंग ग्राउण्ड को अन्य किसी स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शहरी विकास

श्री धन सिंह नेगी
25.01.2019

'19. क्या वन मंत्री अवगत है कि राज्य में वन विभाग द्वारा लीसा डिपो व वन विभाग की चौकियों तक सड़को से आवागमन किया जाता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेगें कि टिहरी जनपद में वन विभाग की ऐसी कितनी सड़के है? क्या यह भी सत्य है कि इन सड़कों से वन भूमि से होकर ग्रामीण भी आवगमन करते है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेगें कि इन सड़कों की लम्बाई तथा चौड़ाई कितनी है? क्या इनसे परिवहन विभाग द्वारा आवागमन के योग्य होने का प्रमाण पत्र लिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

अतारांकित प्रश्न

श्री मनोज रावत
28.12.2018

1. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है? क्या पर्वतीय जिलों में भी इन विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई है? यदि हॉ, तो इन जिला स्तरीय प्राधिकरणों के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिला स्तरीय विकास

आवास

प्राधिकरण आवेदक को क्या सुविधा प्रदान की जाती है?

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
28.12.2018

2. वन मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में 'इको टूरिज्म' के विकास के लिए क्या नीति निर्धारित की गयी है? क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेगें कि सरकार राज्य में 'इको टूरिज्म' डेवलपमैन्ट बोर्ड अथवा ऐसी संस्था की संरचना का विचार करेगी जिसमें सुदूर पर्वतीय अंचलो में भी 'इको टूरिज्म' की गतिविधिया संचालित की जा सके जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके? और पलायन पर रोक लगायी जा सके? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यो? **वन**

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
28.12.2018

3. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में संविदा अथवा अन्य स्रोतों से कार्य कर रहे कार्मिको को श्रम कानूनों के अनुसार विभिन्न प्रकार के लाभ जैसे भविष्य निधि , कर्मचारी बीमा लाभ प्रदान किया जा रहा है? जो विभाग इन श्रम कानूनो का उल्लंघन कर रहे है, उनके विरूद्व कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ताकि श्रमिकों के हित सुरक्षित रह सके? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यो? **श्रम**

श्री देशराज कर्णवाल
02.01.2019

द्वितीय सोमवार के अतारांकित 83 में स्थानान्तरित।

4. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में कितने आवासहीन परिवार हैं तथा झबरेडा विधान सभा क्षेत्र में कितने आवासहीन परिवार हैं? क्या सरकार को इन आवासहीन परिवारों को आवास देने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? **आवास**

श्री नवीन चन्द्र दुम्का
03.01.2019

5. क्या वन मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि उत्तराखण्ड के विधान सभा क्षेत्र लालकुॉ में जौलासाल, हंसपुर, रेखाल, बौड़ खत्ता, खमारी खत्ता, सापकठानी, खस्सीभोज, चीड़खत्ता, तपस्या नाला, हाथगढ़ व तुणीखाल आदि खत्ते है? यदि हॉ, तो मंत्री जी यह बतायेगें कि वन विभाग के दस्तावेज में ये खत्ते किस वर्ष से बसाये गये है, तथा किस योजना के तहत बसाये गये है? **वन**

श्री धन सिंह नेगी
07.01.2019

6. क्या वन मंत्री अवगत है कि राज्य में इको पर्यटन की दृष्टि से कई स्थान उपयोगी है? यदि हॉ, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन–कौन से स्थान चिन्हित किये है? क्या यह भी सत्य है कि इको टूरिज्म से पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेगे? यदि हॉ, तो क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र टिहरी के चंबा, मसूरी, काणाताल, धनोल्टी, राणीचोरी व डंडाचली क्षेत्र को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **वन**

श्री करन माहरा
07.01.2019

7. क्या आवास मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिला विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आ रही परेशानियों को देखते हुए विधान सभा अध्यक्ष पीठ के निर्देशों के क्रम में सरकार ने क्या कदम उठाये है? यदि हॉ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास

श्री धन सिंह नेगी
08.01.2019

8. क्या वन मंत्री अवगत है कि प्रदेश के भारतीय वन सेवा के पदों का विभागीय ढांचा स्वीकृत है? यदि हॉ, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग के स्वीकृत ढांचे में मुख्यालय से जनपद स्तर पर रखे गये अधिकारियों का विवरण क्या है? क्या यह भी सत्य है कि विभाग के मुख्यालय में एक से अधिक मुख्य वन संरक्षक के पदों का सृजन किया गया है? क्या सरकार इन पदों के सृजन का औचित्य बताएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री करन माहरा
08.01.2019

तृतीय सोमवार के अतारांकित–02 में स्थानान्तरित।

9. क्या पुर्नगठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के बाद जिला पुर्नगठन आयोग की कोई बैठक हुई है? यदि हॉ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

पुर्नगठन

श्री गणेश जोशी
08.01.2019

10. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी में मॉल रोड़ की सुन्दरता को बनाये रखने के लिए एक वैंडर जोन का निर्माण कराया जाना उचित होगा? क्या सरकार मसूरी में वैंडर जोन बनाये जाने पर विचार करेगी? यदि हॉ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास

श्री देशराज कर्णवाल
09.01.2019

11. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत है कि बढ़ती आबादी तथा उद्योगों के प्रदूषण से प्रदेश का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? क्या सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने एवं वन क्षेत्र संरक्षण के लिए कोइ ठोस नीति बनाई गई है? यदि हॉ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यावरण

श्री महेन्द्र भट्ट
10.01.2019

12. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आई0टी0आई0 पोखरी (चमोली) में पॉच व्यवसायों के संचालन की स्वीकृति दी गयी थी? यदि हॉ, तो क्या वर्तमान में पॉचों व्यवसायों का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

प्रशिक्षण

श्री महेन्द्र भट्ट
10.01.2019

13. क्या वन मंत्री अवगत है कि जनपद चमोली के दशोली विकास खण्ड में ग्राम भटाकोटी पोस्ट बैरागना निवासी श्री केदारदत्त सेमवाल के नाप खेत में स्थित सुराई वृक्ष के पातन का आदेश उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर द्वारा 14 मार्च 2017 को दिया गया है? यदि हां, तो उक्त वृक्ष के पातन की कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण है?

वन

श्री देशराज कर्णवाल **10.01.2019**	**14.** क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र झबरेडा के अन्तर्गत अभी तक ट्रचिंग ग्राउण्ड प्लांट का निर्माण किया गया है? यदि हॉ, तो उनकी संख्या कितनी है? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शहरी विकास**
श्री देशराज कर्णवाल **11.01.2019**	**15.** क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किन किन जनपदों की नदियों को पुनर्जीवित एवं सौन्दर्यीकरण की योजना बना रखी है? क्या उक्त परियोजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार की किन–किन नदियों को जोड़ा गया है? यदि हां, तो वे कौन कौन सी है? यदि नहीं, तो क्यों ?	**आवास**
श्री देशराज कर्णवाल **14.01.2019**	**तृतीय सोमवार के अतारांकित 03 में स्थानान्तरित।** **16.** क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के सभी अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को सरकार द्वारा रसोई गैस की सुविधा सुनिश्चित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?	**पर्यावरण**
श्री विनोद कण्डारी **14.01.2019**	**17.** क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जंगली जानवरों से निजात पाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उन योजनाओं का नाम सहित सम्पूर्ण विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में विगत 5 वर्षो में जगंली जानवरों द्वारा कुल कितना नुकसान किया गया है तथा उसका सम्पूर्ण विवरण क्या है? क्या सरकार जंगली जानवरों से नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र ही रोक–थाम हेतु कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यो?	**वन**
श्री गणेश जोशी **14.01.2019**	**18.** शहरी विकास मंत्री अवगत है कि क्या मसूरी शहर में नगरपालिका के पास बसें नहीं होने के कारण साधारण जनमानस को आवागमन में असुविधा होती है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से बसे चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शहरी विकास**
श्री देशराज कर्णवाल **15.01.2019**	**19.** क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) के अर्न्तगत आवास मांग सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है? मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेगें कि राज्य के कितने जनपदों में सर्वे पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?	**शहरी विकास**
श्री धन सिंह नेगी **15.1.2019**	**20.** क्या आयुष मंत्री अवगत है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखण्ड राज्य में फार्मेसिस्ट व डाक्टरों की नियुक्तियां की गयी थी? यदि हां तो क्या मत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक उक्त योजना में कितने आयुर्वेद डाक्टर व फार्मेसिस्टो को नौकरियॉ दी गयी है? क्या सरकार एन0एच0एम0 में ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती अस्पतालों में आयुर्वेद डाक्टर व फार्मेसिस्ट रखने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	**आयुष**

श्री देशराज कर्णवाल
16.1.2019

द्वितीय बुधवार के अतारांकित 13 में स्थानान्तरित।

21. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत है कि शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है? क्या सरकार द्वारा किये गये उपायों से यह समस्या दूर हो सकती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **पर्यावरण**

श्री देशराज कर्णवाल
17.1.2019

22. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वन टाइम सेटेलमेंट योजना लागू की गयी है? क्या सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? **आवास**

श्री सरेन्द्र सिंह नेगी
17.01.2019

23. क्या वन मंत्री बतायेगे कि पिटिशन न0 876/2017,878/2018,879/2018,880/2018,883/2017,885/2017,886/2017,889/2017 उत्तरांचल वन श्रमिक संघ बनाम उत्तराखण्ड सरकार में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 5.5.2017 को दिये आदेशानुसार कुमांऊ वन श्रमिक संघ, सेन्टर रानीखेत, को डियरनैस एलाउन्स (महंगाई भत्ता) बकाया राशि 10 हफ्ते के अन्दर 12 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करे, भुगतान न करने की स्थिति में 18 प्रतिशत ब्याज सहित जब तक भुगतान नहीं होता है अदा करेंगे? क्या सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान कर लिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार उक्त आदेशानुसार भुगतान करेगी? यदि हॉ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? **वन**

श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण
17.01.2019

24. क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजाजी टाईगर रिजर्व सहित राज्य के अन्य जंगलों में रह रहे वन गुर्जरों के पुनर्वास के लिए क्या सरकार ने कोई समग्र पुनर्वास नीति बनाई है? यदि हॉ, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है? यदि नहीं, तो इस प्रकार की समग्र पुनर्वास नीति कब तक तैयार कर ली जायेगी एवं इसका क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **वन**

श्री देशराज कर्णवाल
18.01.2019

तृतीय सोमवार के अतारांकित 35 में स्थानान्तरित।

25. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कई वर्षों से कार्यरत संविदा शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु सरकार कोई नियमावली बना रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **प्रशिक्षण**

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी **18.01.2019**	**26.** क्या वन मंत्री बतायेंगे कि सरकार द्वारा सार्वजनिक शमशान घाटों में शव अन्त्येष्टि के लिये लकडी टाल की व्यवस्था का प्राविधान है? यदि हॉ, तो उत्तराखण्ड में कौन–कौन से स्थानों पर वर्तमान में यह व्यवस्था की गयी है? क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के शमशान घाट शिमली, धुनारघाट के समीप शिवालय, मैहलचौरी, माईथान में लकड़ी टाल खोलने की व्यवस्था करेगी? यदि हॉ तो कब तक?	**वन**
श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण **18.01.2019**	**27**. क्या वन मंत्री अवगत है कि राजाजी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत आने वाले पटना गांव में प्राकृतिक जल प्रपात के कारण यहां पर्यटन की असीम संभावना होने के बावजूद इस क्षेत्र का विकास वन कानूनों के कारण नहीं हो पाया है? यदि हॉ, तो क्या राजाजी टाईगर रिवर्ज प्रशासन द्वारा उक्त जल प्रपात के विकास, यहां तक पहुॅचने के रास्तों का उन्नयन आदि के लिये कोई व्यवस्था की जायेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?	**वन**
श्री देशराज कर्णवाल **21.01.2019**	**28**. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि नगर निगम रूड़की के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के मौहल्ला प्रेमनगर, में सीवर लाईनों का कार्य कितना हुआ है? यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो अवशेष क्षेत्र में कार्य कब तक पूरा किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**शहरी विकास**
श्री सहदेव सिंह पुण्डीर **21.01.2019**	**29.** क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून की विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग वन विभाग की सीमा से सटा हुआ है और कई ग्राम पंचायतों के आवागमन का मार्ग वन विभाग क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरता है तथा मार्ग कच्चा व उबड खाबड होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में परेशानी उत्पन्न होती है ? क्या ग्रामवासियों को परेशानी से निजात दिलाये जाने हेतु उक्त मार्गों का निर्माण किये जाने की कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**वन**
श्री प्रीतम सिंह पंवार **23.01.2019**	**30.** क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार नौजवानों की जनपदवार संख्या क्या है? सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के क्या–क्या उपाय किये जा रहे हैं? क्या सरकार विभिन्न जनपदों में पंजीकृत बेरोजगारें को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सेवायोजन**
श्री प्रीतम सिंह पंवार **23.01.2019**	**31.** क्या वन पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट निवारण तथा प्रबन्धन की दिशा में सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किये जा रहे हैं? क्या सरकार बतायेगी कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठोस अपशिष्ट निवारण की समस्या विकराल रूप ले रही है? क्या सरकार ठोस अपशिष्ट निवारण के लिए कोई कारगर योजना बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	**वन**

श्री प्रीतम सिंह पंवार **23.01.2019**	**32.** क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष का मुख्य कारण जंगली जानवरों का गांवों की ओर भोजन एवं पेयजल के लिए आना या पलायन मुख्य कारण हो रहा है ? क्या सरकार वन्य जीवों का जंगलों में ही ठहराव के लिए कोई ठोस व कारगर योजना बना रही है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?	**वन**
श्री प्रीतम सिंह पंवार **23.01.2019**	**33.** क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए ऐसे बाल श्रमिकों के पहचान के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्य किया जाता है? यदि हां, तो राज्य में जनपदवार बाल श्रमिकों की संख्या क्या है? उनके पुर्नवास के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या उपाय किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?	**श्रम**
श्री देशराज कर्णवाल **23.01.2019**	**34.** क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत राज्य के कितने जनपदों के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट परियोजना का संचालन किया जा रहा है? क्या इस योजना से अच्छे परिणाम मिलने लगे है? यदि नहीं, तो क्यों?	**शहरी विकास**
श्री हरभजन सिंह चीमा **23.01.2019**	**35.** क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि काशीपुर शहर की लक्ष्मीपुर माईनर नहर जो शहर के बीचोंबीच होकर ढेला नदी में मिलती है के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में अतिवृष्टि के कारण शहर में भारी मात्रा में जलभराव हो जाता है और शहर के व्यापारियों को प्रतिवर्ष करोड़ों रूपयों की हानि उठानी पड़ती है ? यदि हां तो क्या सरकार द्वारा इस नहर के पुनर्निर्माण हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई है? यदि कार्य योजना बनाई गई है तो उसका स्वरूप क्या है और क्या आने वाली बरसात से पूर्व इस नहर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शहरी विकास**
श्री देशराज कर्णवाल **24.01.2019**	**36.** क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश में नगर निकायों तथा ग्राम पंचायतों के निर्वाचन एवं उनके संचालन हेतु उत्तराखण्ड़ राज्य का अपना अधिनियम तैयार किये जाने की सरकार की कोई योजना है अथवा नहीं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**शहरी विकास**
श्री देशराज कर्णवाल **25.01.2019**	**37.** क्या आयुष मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि आयुष विभाग की नियमावली में आयुष चिकित्सकों को गृह जनपद में तैनाती न किये जाने की व्यवस्था है? क्या मंत्री जी अवगत है कि आयुष चिकित्सक को गृह जनपद में तैनाती दिये जाने से क्षेत्रीय बोली भाषा को समझने से मरीज को उचित उपचार मिल पायेगा क्योंकि आयुष चिकित्सक न तो प्रशासकीय कार्य करते है, और न ही वित्तीय लेन देन ? क्या सरकार क्षेत्रीय जनता के हित एवं उचित उपचार हेतु आयुष चिकित्सकों की नियमावली में संशोधन कर आयुष चिकित्सकों को उनके गृह जनपद में तैनाती दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ?यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?	**आयुष**